

न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 20/2024

1. श्री भंवर मीणा पुत्र उंकार मीणा वनाम निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
2. श्री उदा नाथ पुत्र लाल नाथ निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
3. श्री दूदा रायका पुत्र सोदान रायका निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
4. श्री मुकेश रायका पुत्र भोमा रायका निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
5. श्री रामजश धाकड पुत्र बालू धाकड निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
6. श्री मांगीलाल पुत्र बागा रायका निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
7. श्रीमति मैना देवी पत्नि आशाराम धाकड, सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी भवसागर, तहसील व जिला शाहपुरा।

1. श्री दूदा पुत्र नारायण रेवारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
2. श्रीमति मोरा पत्नी दूदा रेवारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील व जिला शाहपुरा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला शाहपुरा।

—प्रार्थी

—विपक्षी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17-ए राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968

उपस्थित –

1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.04.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17-ए के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि राजस्व केम्प डाबला कचरा में दिनांक 15.12.2004 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम ढाणी भवसागर तह. शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हे. भूमि का आवंटन विपक्षीगण संख्या-01 व 02 को कर दिया, जिसके आवंटन के

जिला कलक्टर
शाहपुरा

बाद तरमीम नंबर 691/154 किये गये। उक्त भूमि ग्राम ढाणी भवसागर तह. शाहपुरा की आराजी संख्या 196 व 232 गेमु नाले के केचमेंट क्षेत्र की भूमि है, जो उम्मेद सागर बांध परियोजना के बहाव क्षेत्र की भूमि होने से विनिश्चय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अनुसार आवंटन योग्य नहीं है। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 का भूमि पर आवंटन के बाद से आज तक भी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा है। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के भूमि आवंटन आवेदन के अंत में सत्यापन नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदन का सत्यापन नहीं होते हुए भी विपक्षीगण का सही सत्यापन मानते हुए व उनका अनुचित पक्ष लेकर उपरोक्त भूमि आवंटन कराने में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर एवं झूठे तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटित कराई है,। विपक्षी संख्या 1 व 2 न तो भूमि आवंटन कराने की पात्रता रखते हैं और न उन्होंने आवंटन नियमों की कोई पालना ही की है। उपरोक्त भूमि का नामान्तरण बिना मौके व तथ्यों की जांच किये खोला गया. उक्त आवंटित भूमि गाम ढाणी भवसागर के मवेशियों के आने जाने का रास्ता वर्षों से चला आ रहा है। भूमि सार्वजनिक उपयोग की तथा उम्मेद सागर बांध के भराव क्षेत्र की व नाले के केचमेंट क्षेत्र की भूमि होने से विपक्षी संख्या 01 व 02 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि एवं नियमों के प्रतिकूल होकर आवंटन नियमों की पालना नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में ग्राम ढाणी भवसागर शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हे. भूमि का किया गया आवंटन दिनांकित 15.12.2004 को अपास्त फरमाया जावे।



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षीगण जवाबदाता को गरीब व भूमिहीन काश्तकार होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सरहद ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 154 में से रकबा 0.25 हैक्टर भूमि का आवंटन की पात्रता रखने के कारण जांच पड़ताल कर विधिवत तौर पर भूमि मजमें आम में आवंटित की गयी जिसमें उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, तहसीलदार, शाहपुरा एवं गिरदावर व आवंटन समिति के सदस्यता के रूप में शामिल थे, जिस पर विपक्षीगण जवाबदाता का मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया, तब से जवाबदाता काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं उससे होने वाली उपज से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं एवं विपक्षी जवाबदाता ने आवंटन कमेटी के समक्ष क्लीन हैड से आवेदन कराया था, आवंटित भूमि किसी प्रकार से गै.मु. नाले के केचमेंट ऐरिया की भूमि नहीं है, न ही अब्दुल रहमान बनाम सरकार का आदेश लागू होता है, उक्त आवंटित भूमि कृषि योग्य भूमि है, जिसमें जवाबदाता विपक्षी का कब्जा होकर काश्त करता चला आ रहा है। वास्तविकता में जवाबदाता की उक्त आराजी पर वक्त आवंटन से काबिज होकर फसल काश्त करता चला आ रहा है। अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। प्रार्थीगण मात्र विपक्षी जवाबदाता को ऐन केन प्रकार से परेशान कर उक्त भूमि को हड़प करना चाहते हैं एवं कोडियों के भाव में लेना चाहते हैं, इसी नियत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। उक्त आवंटन की प्रार्थीगण को शुरु से ही जानकारी है, करीब 15 वर्ष बाद उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। पूर्व में विपक्षी जवाबदाता के गांव एवं समाज के नन्दा, सुरेश, सांवरिया माली ने भी उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अति० जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 01/2017 आ.नि. दर्ज होकर दिनांक

24/10/2019 को आदेश पारित हुआ, जिसमें आवंटन बहाल रखा गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावं।

3. प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा मौखिक बहस एवं लिखित बहस पेश की गई। बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षीगण को ग्राम ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि बाद तरमीम नये नम्बर 691/154 आवंटन दिनांक 15.12.2004 का आवंटन नियम विरुद्ध किया गया। विपक्षीगण ने पति पत्नी होते हुए मां बेटे के रूप में आवंटन करा लिया और बाद में बिना कानूनी कार्यवाही किये बगैर कागजों में हेर फेर करते हुए वापस नाम सुधार करा लिया। आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक विपक्षीगण द्वारा फसल काशत नहीं की गई है। खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2066 से 2069 संलग्न है। आवंटित भूमि मौके पर आम सड़क व सार्वजनिक उपयोग के काम में आ रही है। मौके के फोटो ग्राफ संलग्न है। आवंटित भूमि ग्राम ढाणी भवसागर की आराजी संख्या 196 व 232 मेरमुनकिन नाले की कंचमेन्ट क्षेत्र की भूमि है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन को निरस्त करने का आदेश प्रदान करना फरमावें।



विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में मुख्य आधार विपक्षीगण जवाबदाता आवंटी का कच्चा नहीं होना बताया है, जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण काशत करते चले आ रहे हैं व वर्तमान में भी गेहू की फसल काशत की गयी है। उक्त जमीन के खसरा गिरदावरी वर्ष 2024 संवत् 2080 रबी (उन्हालू) जो कि दिनांक 03.04.2024 को ऑनलाईन प्राप्त की गयी है, जिसमें भी गेहू की फसल बोना अंकित कर रखा है, जिसकी नकल संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण का मौके पर कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा दूसरा मुख्य आधार आवंटित भूमि जो कि कंचमेन्ट एरिया की भूमि होना बताया है, जबकि उक्त भूमि कंचमेन्ट एरिया की भूमि नहीं है व न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि कंचमेन्ट एरिया में आने बाबत कोई दस्तावेज पेश किये हैं व न ही कंचमेन्ट एरिया में आने की रिपोर्ट पत्रावली पर आयी है व साथ ही उक्त भूमि किसी भी प्रकार से कोई बहाव क्षेत्र में नहीं आती है, यहां पर किसी प्रकार का बहाव नहीं होता है, न ही पानी के बहाव को रोका जाता है व न ही पेटा काशत की जमीन है, बल्कि खसरा गिरदावरी में किस्म वीड अंकित है, जो खसरा गिरदावरी हमराह लिखित बहस पेश है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि कंचमेन्ट एरिया की भूमि नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भर्त्साती परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को ग्राम ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा की आराजी संख्या 154 में रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि बाद तरमीम नये नम्बर 691/154 आवंटन दिनांक 15.12.2004 का आवंटन नियम विरुद्ध किया गया। लेकिन उक्त संवध में पत्रावली में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। केवल फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कराये गये हैं, लेकिन उक्त फोटोग्राफ्स से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त फोटो विपक्षीगण को आवंटित भूमि की फोटो है। प्रार्थी ने बताया की आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक विपक्षीगण द्वारा फसल काशत नहीं की गई है। जबकि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी वर्ष 2024 संवत् 2080 रबी (उन्हालू) जो कि दिनांक

जिला कलक्टर
शाहपुरा


03.04.2024 को ऑनलाईन प्राप्त की गयी है, जिसमे भी गैहू की फसल बोना अंकित कर रखा है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण का मौके पर कब्जा काशत है। प्रार्थी ने बताया की आवंटित भूमि मौके पर आम सड़क व सार्वजनिक उपयोग के काम में आ रही है एवं आवंटित भूमि ग्राम ढाणी भवसागर की आराजी संख्या 196 व 232 गेरमुमकिन नाले की केचमेन्ट क्षेत्र की भूमि बताई गई है। इस संदर्भ में न तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि केचमेन्ट एरिया में आने बाबत कोई दस्तावेज पेश किये है व न ही केचमेन्ट एरिया में आने की रिपोर्ट पत्रावली पर आयी है व साथ ही उक्त भूमि किसी भी प्रकार से कोई बहाव क्षेत्र में नहीं आती है, यहां पर किसी प्रकार का बहाव नहीं होता है, न ही पानी के बहाव को रोका जाता है व न ही पेटा काशत की जमीन है, बल्कि खसरा गिरदावरी में किस्म बीड़ अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि केचमेन्ट एरिया की भूमि नहीं है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 की पालना किया जाना स्पष्ट होता है। जहां तक विस्तृत रूप से खातेदारी के समय परीक्षण की जरूरत है वहां खातेदारी देने से पहली काशत वगैरह के मानक जैसे ही देखे जाते है। यदि प्रकरण खातेदारी देने का नहीं बनेगा तो राजस्व प्राधिकारी कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17-ए अस्वीकार योग्य ठहरता है।

आदेश

6. अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17-ए बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार कर किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

7. निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
जिशाहपुरा कलक्टर
साहपुरा